पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति कटिबद्ध : मुख्यमंत्री

महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ–साथ राज्य सरकार उनकी सुरक्षा एवं आत्म सम्मान की रक्षा के लिए सभी प्रयास कर रही है : मुख्यमंत्री

केन्द्र एवं राज्य की सरकारें महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति अत्यन्त संवेदनशील

आज महिलाएं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और संवैधानिक पदों पर पूरी कर्मठता महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं : मुख्यमंत्री

मातृशक्ति को प्रोत्साहित करने के साथ–साथ सामाजिक जागरूकता महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक : मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं के कल्याण व उत्थान के लिए निरन्तर प्रयासरत : मुख्यमंत्री

राज्य सरकार महिलाओं एवं बालिकाओं को पूरी सुरक्षा देने के साथ–साथ उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कृतसंकल्पित

मुख्यमंत्री ने 'अपराजिता 100 मिलियन स्माइल्स' अभियान को लॉन्च किया

सभी जिलाधिकारियों को धान खरीद के विषय में वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए : मुख्यमंत्री

लखनऊ : 16 नवम्बर, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ–साथ राज्य सरकार उनकी सुरक्षा एवं आत्म सम्मान की रक्षा के लिए सभी प्रयास कर रही है। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए '1090' विमेन पावर लाइन तथा '181' महिला हेल्प लाइन संचालित की जा रही हैं। इसके अलावा एण्टी रोमियो स्क्वॉयड का भी गठन राज्य सरकार द्वारा पूर्व में किया जा चुका है, ताकि महिलाओं और बालिकाओं को असामाजिक तत्वों से सुरक्षा प्रदान की जा सके।

मुख्यमंत्री जी ने यह विचार आज यहां अपने सरकारी आवास पर दैनिक अमर उजाला द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे नारी गरिमा के साझा संकल्प अभियान 'अपराजिता 100 मिलियन स्माइल्स' को लॉन्च करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि केन्द्र एवं राज्य की सरकारें महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति अत्यन्त संवेदनशील हैं। आज महिलाएं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और संवैधानिक पदों

पर पूरी कर्मठता से महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं। महिलाओं की जागरूकता, स्वावलम्बन और उन्हें सभी सुविधाओं को समान रूप से प्रदान करने के लिए समाज व परिवार को आगे आना होगा। यदि सभी महिलाओं में जागरूकता आ जाए, तो समस्त क्षेत्रों में उन्नति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मातृशक्ति को प्रोत्साहित करने के साथ–साथ सामाजिक जागरूकता महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों द्वारा समाज व देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज महिलाएं सभी क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रही हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उन्होंने कहा कि जीवन व समाज में उल्लेखनीय बदलाव के लिए सकारात्मक व अच्छी सोच आवश्यक है। नारी प्रगति के लिए स्वयं, अन्य लोगों, परिवार व समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना होगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नारी शक्ति में व्यापक जागरूकता लाने के लिए परिवार, विभिन्न संस्थाओं तथा समाज के योगदान की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज लोकसभा अध्यक्ष, विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएं कार्य कर रही हैं। देश के कई राज्यों में गवर्नर के रूप में भी महिलाएं अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं। एशियन गेम्स में भी बालिकाओं ने अपनी सफलता का परचम लहराया है। इतना ही नहीं, प्रदेश की हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट जैसी परीक्षाओं में भी बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत अधिक है। मेरिट में भी छात्राओं का स्थान ऊपर है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं के कल्याण व उत्थान के लिए निरन्तर प्रयासरत है। प्रधानमंत्री जी ने बेटियों से होने वाले भेदभाव को समाप्त करने और उनको हक दिलाने के लिए 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना संचालित की है। स्वच्छ भारत मिशन तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत भी महिलाओं की स्वीकार्यता बढ़ी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण कराया गया है। इस मिशन ने जनान्दोलन का रूप ले लिया है। स्वच्छता को बढ़ावा देने के साथ–साथ शौचालय निर्माण महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से प्रदेश में बड़ी संख्या में गरीब महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं एवं बालिकाओं को पूरी सुरक्षा देने के साथ–साथ उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कृतसंकल्पित है। उन्हें समान अवसर देने के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं।

महिलाओं की सुरक्षा तथा देश व प्रदेश के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूर्व सरकारों द्वारा राज्य के सरकारी सिस्टम को काफी बिगाड़ा गया, लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा इसे वापस पटरी पर लाने का काम किया गया है। उन्होंने उम्मीद जतायी कि लोगों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार स्वार्थ नहीं, बल्कि परमार्थ के लिए कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री जी ने वर्तमान में पूरे प्रदेश में चल रही धान खरीद के विषय में कहा कि कल (15 नवम्बर, 2018) आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। छोटे किसानों के हित को देखते हुए उन्हें सत्यापन व्यवस्था से मुक्त कर दिया गया है। कोई भी किसान 100 कुन्तल तक धान पंजीकरण के बाद बेच सकता है। पूर्व में पंजीकृत समितियों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज व फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन को सीमान्त एवं लघु कृषकों से अधिकतम 25 कुन्तल व 50 कुन्तल खरीदने की अनुमन्यता थी। अब इन किसानों से जिले की उत्पादकता के आधार पर धान क्रय किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष समर्थन मूल्य योजना के तहत कॉमन श्रेणी के धान के लिए 1750 रुपये प्रति कुन्तल का मूल्य निर्धारित किया गया है, जबकि ग्रेड ए धान के लिए 1770 रुपये प्रति कुन्तल का मूल्य रखा गया है। इसके अलावा, किसानों को उतराई व छनाई के मद में इस वर्ष 20 रुपए प्रति कुन्तल अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। प्रदेश में मक्के की खरीद के सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि पहली बार इसकी खरीद 15 नवम्बर, 2018 से 20 जनपदों में प्रारम्भ की जा रही है। इसके लिए 100 क्रय केन्द्रों के माध्यम से 01 लाख मीट्रिक टन मक्का खरीद का कार्यकारी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस वर्ष 121 चीनी मिलों का संचालन किया जाएगा। इनमें से 71 चीनी मिलें संचालित हो चुकी हैं तथा शेष चीनी मिलें 25 नवम्बर, 2018 तक संचालित कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। इसके भुगतान के लिए 4000 करोड़ रुपए की ऋण की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई है, जिसके तहत चीनी मिलों द्वारा आवेदन बैंकों में प्रस्तुत कर दिए गए हैं। शासन द्वारा प्रथम किश्त में 1000 करोड़ रुपए अवमुक्त किए जा चुके हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने 'अपराजिता 100 मिलियन स्माइल्स' पत्रिका का विमोचन भी किया।